श्री विजयलक्ष्मी चावल मिल्स, नई ठेकेदार कंपनी आदि

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य

22 मार्च, 1976

[ए.एन. राय, (सीजे), एम. हमीदुल्लाह बेग, और जसवंत सिंह, जे.जे.]

चावल (आंध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश 1964, खंड 2- क्या स्पष्ट प्रावधान के अभाव में प्रतिस्थापन की पूर्वव्यापीता का अनुमान लगाया गया है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत, प्रतिवादी ने आंध्र प्रदेश खरीद (लेवी) आदेश 1959 पारित किया, जिसके तहत चावल के प्रत्येक मिलर और डीलर (अपीलकर्ताओं सहित) को प्रतिवादी को कुछ निर्दिष्ट किस्मों और मात्रा में चावल को नियंत्रित मूल्य पर बेचना वांछित है जब उसकी मांग की जाए। आदेश के खंड 2(ए) में "नियंत्रित मूल्य" को चावल की बिक्री के लिए अधिनियम की धारा 3 के तहत समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। 19 दिसंबर, 1963 को केंद्र सरकार ने चावल (आंध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश 1963 पारित किया, जिसमें अक्कुलु चावल की अधिकतम

कीमत 46.89 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई। अपीलकर्ताओं ने 26 जनवरी, 1964 से 21 फरवरी, 1964 तक प्रतिवादी को कई मात्रा में अक्कुलु चावल बेचे और उन्हें नियंत्रित दर पर भुगतान किया गया। 23 मार्च, 1964 को, केंद्र सरकार ने चावल (आंध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश 1964 जारी किया, और अक्कुलु चावल की प्रति क्विंटल अधिकतम कीमत 46.89 रुपये के स्थान पर 52.28 रुपये कर दी। पिछली बिक्री के लिए बढ़ी हुई कीमत के लाभ के अपीलकर्ता के दावे को आंध्र प्रदेश सरकार ने खारिज कर दिया। अपीलकर्ता दो नियंत्रित कीमतों के बीच अंतर की वसूली के लिए अपने मुकदमे में मछलीपट्टनम के अधीनस्थ न्यायाधीश के समक्ष सफल हुए, लेकिन आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा की गई अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष हार गए। इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि सरकार द्वारा तय की गई कीमतें पूरे सीज़न के लिए हैं, और अपीलकर्ता आपूर्ति की गई तारीखों की परवाह किए बिना संशोधित दरों पर भुगतान के हकदार हैं, और "विकल्प" शब्द पूर्वव्यापी प्रभाव को दर्शाता है।

अपीलों को खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि: स्पष्ट शब्दों या उपयुक्त भाषा के अभाव में, जिससे पूर्वव्यापीता का अनुमान लगाया जा सके, अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होती है, न कि किसी पूर्व तारीख से। क़ानूनों का अर्थ इस प्रकार नहीं लगाया जाना

चाहिए कि वे उन लेन-देन के संबंध में नई अक्षमताएं या दायित्व पैदा करें या नए कर्तव्य लागू करें जो संशोधन अधिनियम लागू होने के समय पूर्ण हो गए थे। [778 बी-सी]

(2) माल में संपत्ति आपूर्ति की तारीखों को आंध्र प्रदेश सरकार को पारित करने के बाद, अपीलकर्ताओं को केवल बिक्री की तारीखों पर प्राप्त नियंत्रित कीमतों पर भुगतान किया जाना था, न कि बढ़ी हुई कीमत पर जो बाद में लागू हुई। [778-डी]

के. अप्पय्या शानभागे एंड कंपनी बनाम मैसूर राज्य और अन्य (असूचित निर्णय एससी दिनांक 20-4-1962); भारत संघ खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सचिव द्वारा प्रतिनिधित बनाम कनुरी दामोदरिया एंड कंपनी अल्लूरी वेंकटनरसिया (1968) 1 एएन. डब्ल्यू आर 81 और मणि गोपाल मित्रा बनाम बिहार राज्य (1969) 2 एससीआर 411, अनुसरण किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 805, 806 और 972-977/1973

अपील सूट संख्या क्रमशः 766/1968, 18/1969, 779, 780, 782 से 785/1968 में हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के क्रमशः 8 जून 1971 और 23 नवंबर 1971 के निर्णय और डिक्री से।

अपीलकर्ताओं के लिए एफएस नरीमन, जेवीके गुरुनाथन, टीवी नरसिम्हन मूर्ति और ए सुभा राव।

प्रतिवादियों की ओर से पी. राम रेड्डी और पी.पी. राव।

न्यायालय का निर्णय जसवन्त सिंह, जे. द्वारा सुनाया गया। अपील संख्या 766/1968, 18/1969, 779/1968, 780/1968, 782/1968, 783/1971, 784/1968 और 785/1968 में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के निर्णयों और डिक्री से प्रमाण पत्र द्वारा अपील संख्या 805, 806 और 972 से 977/1973 तक का यह बैच एक सरल लेकिन दिलचस्प सवाल उठाता है, कि क्या अपीलकर्ताओं द्वारा जनवरी और फरवरी, 1964 में की गई चावल की आपूर्ति के लिए, उन्हें चावल (आंध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, 1964 दिनांक 23 मार्च, 1964 में निर्दिष्ट दर के अनुसार मूल्य का भुगतान किया जाना है या चावल (आंध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश में निर्दिष्ट दर के अनुसार, जैसा कि 1963 में था। प्रश्न निम्नलिखित परिस्थितियों में उठता है:

अपीलकर्ता मिल मालिक हैं और आंध्र प्रदेश राज्य में धान और चावल का व्यवसाय करते हैं। 31 जुलाई, 1959 को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केंद्रीय अधिनियम X) की धारा 3 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में जाना जाएगा, आंध्र प्रदेश चावल खरीद (लेवी) आदेश, 1959 नामक एक आदेश दिया। आदेश के खंड 3 में प्रत्येक डीलर और प्रत्येक मिलर को नियंत्रित मूल्य पर मांग प्राधिकारी द्वारा दी गई मांग पर राज्य सरकार को बेचने की आवश्यकता थी (ए) आदेश के लागू होने पर उसके द्वारा स्टॉक में रखे गए चावल की मात्रा का 40 प्रतिशत और (बी) आदेश के लागू होने के बाद हर दिन उसके द्वारा खरीदे गए चावल की कुल मात्रा का 40 प्रतिशत। आदेश के खंड 2 (ए) में "नियंत्रित मूल्य" को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर चावल की बिक्री के लिए अधिनियम की धारा 3 के तहत निर्धारित अधिकतम मूल्य (बल दिया गया)। 19 दिसंबर, 1963 को, केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एक आदेश दिया, जिसे चावल (आंध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, 1963 कहा गया, जो आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा, पश्चिम गोदावरी, पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, निज़ामाबाद, वारंगल और नेल्लोर जिलों तक विस्तृत था। आदेश के खंड (2) में प्रावधान किया गया है कि उस आदेश की अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट चावल की किस्मों को उन अधिकतम कीमतों पर थोक में बेचा जाना था जैसा कि उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टियों में निर्दिष्ट है। उक्त अनुसूची में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि अक्कुलु चावल 46.89 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचा जाएगा।आंध्र प्रदेश राज्य के मांग प्राधिकारी द्वारा उन्हें दी गई मांगों के अनुपालन में,

अपीलकर्ताओं ने 26 जनवरी, 1964 से 21 फरवरी, 1964 तक उस राज्य की सरकार को उस किस्म के चावल की विभिन्न मात्रा बेची, और उन्हें पूर्वोक्त दर 46.89 प्रति क्विंटल भुगतान किया गया। चावल (आंध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 1964 दिनांक 20 मार्च, 1964 के माध्यम से, केंद्र सरकार ने चावल (आंध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, 1963 के खंड 2 के उप-खंड (1) में संशोधन किया और नियत किया गया है कि उक्त उपखंड में "अनुसूची" शब्दों के स्थान पर अनुसूची 1 शब्द और अंक रखे जाएंगे। 23 मार्च, 1964 को केंद्र सरकार ने चावल (आंध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, 1964 जारी किया। आदेश का खंड 2 इस प्रकार है:-

2. चावल (आंध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, 1963 में, अनुसूची । में, चावल की किस्मों और उसके बाद की अधिकतम कीमतों के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

चावल की किस्मे	अधिकतम मूल्य प्रति क्विंटल
1. नेल्लोर के अतिरिक्त अन्य जिले	
अक्कूलु	52-25

इस आदेश के जारी होने पर, अपीलकर्ताओं ने आंध्र प्रदेश सरकार को अभ्यावेदन देकर अनुरोध किया कि 26 जनवरी से 21 फरवरी, 1964 तक

उनके द्वारा की गई अक्कुलु चावल की उपरोक्त आपूर्ति के लिए, उन्हें 52.25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ी हुई कीमत पर भुगतान किया जाना चाहिए। चूंकि उनके द्वारा किए गए अभ्यावेदन को अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली, उन्होंने चावल (आंध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, 1963, दिनांक 19 दिसंबर, 1963 और चावल (आंध्र प्रदेश), मूल्य नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, 1964 में निर्दिष्ट नियंत्रित कीमतों के बीच अंतर की वसूली के लिए मछलीपट्टनम के अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत में मुकदमा दायर किया। उनके द्वारा दायर मुकदमों पर उस न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया था। इन निर्णयों और आदेशों से व्यथित होकर, आंध्र प्रदेश राज्य ने हैदराबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर की, जिसे इस आधार पर अनुमति दी गई थी कि चावल (आंध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, 1964 से पहले अपीलकर्ताओं द्वारा चावल की आपूर्ति की गई थी, वे केवल चावल (अंधरा प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, 1963 की अनुसूची में निर्दिष्ट मूल्य के हकदार थे। इन निर्णयों और आदेशों से असंतुष्ट अपीलकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 133(1)(ए) के तहत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जो उन्हें प्रदान किया गया।

इन अपीलों में निर्धारण के लिए एकमात्र प्रश्न, जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, यह है कि क्या अपीलकर्ताओं को 26 जनवरी, 1964 से 21 फरवरी, 1964 तक उनके द्वारा की गई चावल की आपूर्ति के लिए

चावल (आंध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, 1963, दिनांक 19 दिसंबर, 1963 में निर्दिष्ट दर 46.89 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाना था या चावल (आंध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, 1964 दिनांक 23 मार्च, 1964 द्वारा निर्धारित बढ़ी हुई दर 52.25 रुपये प्रति क्विंटल की दर से।

अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित श्री नरीमन ने चावल (आंध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, 1964 के खंड 2 में आने वाले शब्द "प्रतिस्थापित" पर बहुत जोर दिया है और आग्रह किया है कि अपीलकर्ताओं का दावा खारिज नहीं किया जा सकता है। अपनी दलील को विस्तार से बताते हुए, अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि चूँकि सरकार द्वारा निर्धारित कीमतें पूरे सीज़न के लिए होती हैं, इसलिए अपीलकर्ताओं को, उन तारीखों की परवाह किए बिना जिन पर आपूर्ति की गई थी, चावल (आंध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, 1964 के तहत निर्धारित नियंत्रित मूल्य पर भुगतान करना होगा। हम इस विवाद को स्वीकार नहीं कर सकते। इसमें कोई संदेह नहीं है कि "स्थानापन्न" शब्द का शाब्दिक अर्थ "प्रतिस्थापित करना' है, लेकिन हमारे सामने प्रश्न यह है कि नई अनुसूची का प्रतिस्थापन या रिप्लेसमेंट किस तारीख से प्रभावी हुआ। इसमें कोई डीमिंग क्लॉज या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है चावल (आंध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, 1964 यह इंगित करने के

लिए कि इसका उद्देश्य पूर्वव्यापी प्रभाव डालना था। यह व्याख्या का एक सर्वमान्य नियम है कि स्पष्ट शब्दों या उचित भाषा के अभाव में, जिससे पूर्वव्यापीता का अनुमान लगाया जा सके, अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होती है, न कि किसी पूर्व तारीख से। यह सिद्धांत भी सुस्थापित है कि क़ानूनों का अर्थ इस तरह नहीं लगाया जाना चाहिए कि इससे नई अक्षमताएं या दायित्व पैदा हों या उन लेनदेन के संबंध में नए कर्तव्य लगाए जाएं जो संशोधन अधिनियम लागू होने के समय पूरे हो गए थे। (मणि गोपाल मित्रा बनाम बिहार राज्य ([1969 2 एस.सी.आर. 411 देखें)

चावल (आंध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, 1964 के लागू होने से पहले अपीलकर्ताओं द्वारा वर्तमान मामलों में उपरोक्त बिक्री की गई थी और आपूर्ति की तारीखों पर आंध्र प्रदेश सरकार को हस्तांतरित माल में संपत्ति, अपीलकर्ताओं को केवल बिक्री की तारीखों पर प्राप्त नियंत्रित मूल्य पर भुगतान किया जाना था, न कि बढ़ी हुई कीमत पर जो बाद में लागू हुआ था। यह दृष्टिकोण अधिनियम की धारा 3 और आंध्र प्रदेश चावल खरीद (लेवी) आदेश, 1959 के प्रावधानों के अनुरूप है जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि डीलरों और मिलर्स को उनके द्वारा की गई चावल की आपूर्ति के लिए देय मूल्य बिक्री की तारीख पर प्राप्त होने वाला नियंत्रण मूल्य है। इसी तरह का दृष्टिकोण के. अप्पय्या शंभागुए एंड कंपनी बनाम मैसूर राज्य और अन्य मामले में इस न्यायालय के 20 अप्रैल, 1962 के

असूचित निर्णय में अपनाया गया है। जहां यह निर्धारित किया गया था कि अधिनियम की धारा 3 (2)(एफ) के तहत किए गए आदेश बिक्री के प्रस्ताव हैं, जिसे जिस व्यक्ति को मांग दी गई है, उसके पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और भुगतान की जाने वाली कीमत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3(2)(सी) के तहत उस तिथि पर निर्धारित नियंत्रित मूल्य है जब माल का निर्धारण किया जाता है या जब माल में संपत्ति खरीदार के पास जाती है। इस निर्णय का पालन भारत संघ में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा किया गया, जिसका प्रतिनिधित्व सचिव, खाद्य और कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली बनाम कनुरी दामोदरिया एंड कंपनी अल्लूरी वेंकटनारसिया ने किया, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 3(2) (एफ) के तहत एक आदेश बिक्री के लिए एक समझौते के समान है और आपूर्ति किए गए चावल की मात्रा के लिए देय मूल्य अधिनियम की धारा 3 (3) के प्रावधानों के तहत अधिसूचित मूल्य के अनुसार देय मूल्य है।

वर्तमान मामलों में, बिक्री चावल (आंध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, 1964 के लागू होने से पहले की गई है, अपीलकर्ता उचित रूप से चावल (आंध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (तृतीय संशोधन) आदेश, 1964 में निर्दिष्ट बढ़ी हुई कीमत के लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं।

अपीलकर्ताओं की ओर से उठाए गए तर्कों को स्वीकार करने के गंभीर परिणाम होंगे। इसका प्रभाव पुराने और समाप्त हो चुके लेन-देन को फिर से खोलने पर पड़ेगा और इस प्रकार बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाएंगी।

श्री नरीमन ने, अपने तर्क के समर्थन में, क्रेज़ ऑन स्टैट्यूट लॉ (छठा संस्करण) के पृष्ठ 394 पर आने वाले निम्नलिखित परिच्छेद पर भरोसा किया है:-

"व्याख्यात्मक और घोषणात्मक अधिनियम पूर्वव्यापी

जहां किसी क़ानून को पूर्व क़ानून में स्पष्ट चूक को लागू करने के उद्देश्य से पारित किया जाता है, या, जैसा कि पार्क जे (बाद में बैरन पार्क) ने आर वी डस्र्ली (1832) 3 बी और विज्ञापन 465, 469 में कहा था "किसी पूर्व क़ानून को समझाने के लिए," बाद के क़ानून का संबंध उस समय से है जब पिछला अधिनियम पारित किया गया था। इस प्रकार अट.-जनरल बनाम पॉट्ट (1816) 2 मूल्य 381, 392 में, ऐसा प्रतीत होता है कि 1873 के सीमा शुल्क अधिनियम (53 जियो 3, सी 33) द्वारा 9 एस 4 डी के पशुचर्म पर एक शुल्क लगाया गया था, लेकिन अधिनियम यह बताने से

चूक गया कि यह 9 एस 4 डी प्रति सीडब्ल्यूटी होना था, और इस चूक को ठीक करने के लिए उसी वर्ष बाद में एक और सीमा शुल्क अधिनियम (53 जियो सी 105) पारित किया गया।इन दोनों अधिनियमों के पारित होने के बीच कुछ खालें निर्यात की गईं, और यह तर्क दिया गया कि वे शुल्क 9 एस 4 डी प्रति सीडब्ल्यूटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे, लेकिन थॉमसन सीबी ने अटॉर्नी जनरल के लिए निर्णय देते हुए कहा: "इस प्रकरण में शुल्क वास्तव में पहले अधिनियम द्वारा लगाया गया था, लेकिन महत्वपूर्ण चूक जिसके लिए व्यक्त की गई राशि देय थी, बाद के अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन के कारण हुई, लेकिन इसका संदर्भ पूर्व से था जैसे ही क़ानून पारित हुआ, और उन्हें एक साथ लिया जाना चाहिए जैसे कि वे एक ही अधिनियम थे।"

जहां कोई अधिनियम अपनी प्रकृति में घोषणात्मक है, वहां इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू करने के खिलाफ धारणा लागू नहीं होती है।"

हमारी राय में, इस अनुच्छेद का इस तथ्य के मद्देनजर हमारे सामने मौजूद प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं है कि चावल (आंध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (तीसरा

संशोधन) आदेश, 1964 न तो व्याख्यात्मक है और न ही घोषणात्मक, जैसा कि अधिवक्ता द्वारा व्याख्या करने की मांग की गई है।

श्री नरीमन का यह तर्क भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि चावल की बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित कीमतें मौसमी कीमतें हैं जो किसी ठोस सामग्री पर आधारित नहीं हैं।

इसलिए, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा की गई उपरोक्त अपीलों को स्वीकार करके और अधीनस्थ न्यायाधीश, मछलीपट्टनम द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को पलटकर सही कदम उठाया।

परिणामस्वरूप, अपील विफल हो जाती है और एक सेट तक सीमित लागत के साथ खारिज कर दी जाती है।

एमआर अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक खुशबू सोनी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।